भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3310

उत्तर देने की तारीख- 16/12/2024

विदेश में अध्ययनरत छात्रों द्वारा वित्तीय बहिर्वाह

†3310. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2025 तक विदेश में अध्ययनरत भारतीय छात्रों द्वारा लगभग 70 बिलियन डॉलर के महत्वपूर्ण वित्तीय बहिर्वाह, विशेष रूप से देश के भीतर उपलब्ध शैक्षिक अवसरों के संबंध में, का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) सरकार किस प्रकार कनाडा के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाकर भारतीय छात्रों के लिए अधिक शैक्षिक भागीदारी और अवसर सृजित करने की योजना बना रही है, जिससे उन्हें विदेश में अध्ययन करने की आवश्यकता कम हो;

(ग) क्या सरकार अन्य देशों में भारतीय छात्रों द्वारा किए जाने वाले धन के प्रवाह के संबंध में देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने विशेष रूप से इन छात्रों द्वारा देश में शिक्षा प्राप्त करने पर न मिल पाए संभावित आर्थिक योगदान के संदर्भ में इस वित्तीय बहिर्वाह से संबंधित अवसर लागतों पर कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): विदेश में अध्ययन करना व्यक्तिगत इच्छा और पसंद का मामला है। भारत सरकार ने भारत में प्रत्येक स्तर पर उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। देश में शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव और सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 तैयार की गई और उसे मंजूरी दी गई। एनईपी 2020 के प्रमुख पहलुओं में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा की ओर बढ़ना, संस्थागत स्वायत्तता, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा देना, कौशल

विकास, शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास, प्रौद्योगिकी का एकीकरण, उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, बहु-विषयक पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, मिश्रित मूल्यांकन और भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है।

भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन, संस्थानों और पाठ्यक्रमों की मान्यता, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के माध्यम से कई पहल की हैं। इनमें से कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) योजना तीन घटकों (i) चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाना, (ii) विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढाँचा अनुदान, और (iii) बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू) के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश पाने वाले किसी भी छात्र को सहायता प्रदान करना है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए **राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी)** के माध्यम से उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) की मान्यता को बढ़ावा देना।
- **राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए)** द्वारा डिप्लोमा स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणात्मक क्षमता का आकलन करना।
- नवाचार, ज्ञान सृजन के लिए केंद्र के रूप में कार्य करने और शीर्ष-निर्धारित उद्योगों के साथ अनुसंधान सहयोग करने, छात्रों की उद्यमशीलता और इनक्यूबेशन को सक्षम करने और मजबूत शैक्षणिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रमुख संस्थानों में **8 अनुसंधान पार्क** स्थापित किए गए।
- अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देना, विकसित करना और प्रवर्तन करना तथा भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और आरएंडडी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- **अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएआरसी)** जिसका उद्देश्य प्रमुख विदेशी संस्थानों के साथ शीर्ष भारतीय संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करना है;
- देश भर के छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संसाधनों, शोध पत्रों और पत्रिकाओं तक केंद्रीकृत पहुँच प्रदान करने के लिए **एक राष्ट्र, एक सदस्यता पहल**;

- **स्वयम, स्वयम प्लस** आदि के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी को उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री सुनिश्चित करना:
- स्वास्थ्य सेवा, कृषि और दीर्घकालिक शहरों पर केंद्रित तीन कृत्रिम बुद्धिमता आधारित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता देना शामिल है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहल- **भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एफएचईआई) की स्थापना और संचालन के लिए नियम**, **संयुक्त/दोहरी/ट्विनिंग डिग्री कार्यक्रमों** के लिए अकादमिक सहयोग, **इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम** के लिए दिशा-निर्देश, **उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठों की स्थापना**, **प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस** की अवधारणा को बढ़ावा देना, **उच्चतर शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए सुगम्यता संबंधी दिशा-निर्देश और मानक,** एनईपी 2020 की उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए **उत्साह पोर्टल** (उच्चतर शिक्षा में परिवर्तनकारी रणनीति और कार्य करना) शुरू करना, **जीवन कौशल (जीवन कौशल) 2.0 पर पाठ्यक्रम और दिशा-निर्देश जारी करना, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम** आदि हैं ।

विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत और कनाडा के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग विभिन्न तंत्रों के माध्यम से सुगम बनाया जाता है, जिसमें समझौता ज्ञापन (एमओयू), शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच व्यक्तिगत साझेदारी, छात्र और शिक्षक आदान-प्रदान, अन्य पहल शामिल हैं।

'स्टडी इन इंडिया' (एसआईआई) कार्यक्रम भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत को उच्चतर शिक्षा के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए वर्ष 2018 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। वर्ष 2020 में तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया गया था, जिसमें भारत में शिक्षा की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, संस्थान की उच्च प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि/रैंकिंग और पाठ्यक्रम का मूल्य और विशिष्ट पाठ्यक्रम की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया था। इसके बाद, एसआईआई कार्यक्रम को नया रूप दिया गया और वर्ष 2021-2026 की अवधि के लिए जारी रखा गया। इसके अलावा, भारत में विदेशी छात्रों की निर्बाध आवाजाही की सुविधा के लिए, स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) पोर्टल https://studyinindia.gov.in को 3 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया।

*****